शनिवार 16 मई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

'अंधेरा' कमेंट पर विवाद, मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा के अंदाज में दिया जवाब

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

वेलकम टू द जंगल का टीजर रिलीज

Page-05

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पांच देशों के दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से की। अबू धाबी में उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति के साथ ऊर्जा, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

अबू धाबी में भव्य स्वागत F-16 विमानों ने दी सुरक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने पांच देशों के महत्वपूर्ण विदेश दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से की। 15 से 20 मई तक चलने वाले इस दौरे में प्रधानमंत्री यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक, हरित विकास और निवेश जैसे क्षेत्रों में भारत की वैश्विक साझेदारियों को और मजबूत करना है।प्रधानमंत्री मोदी के विमान के यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां की वायु सेना के एफ-16 लड़ाकू विमानों ने उन्हें एयर एस्कॉर्ट प्रदान किया। यह सम्मान भारत और यूएई के बीच मजबूत रणनीतिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है।अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। खास बात यह रही कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान स्वयं हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मौजूद रहे, जिसे दोनों देशों के गहरे संबंधों का संकेत माना जा रहा है।प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया, वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। हालांकि, मौजूदा हालात में यूएई ने जिस संयम और संतुलन के साथ स्थिति को संभाला है, वह सराहनीय है।"प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चुनौतियों को महसूस कर रही है। उन्होंने दोहराया कि भारत शांति और स्थिरता के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।गौरतलब है कि अमेरिकी-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान संयुक्त अरब अमीरात भी ईरानी हमलों का निशाना बना है। यूएई में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा भी मौजूद है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी यूएई के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने लिखा, "अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए मैं अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारत और यूएई के बीच ऊर्जा, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए होने वाली चर्चाओं को लेकर उत्साहित हूं।"विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी यूएई में लगभग चार घंटे बिताएंगे, जिसके बाद वे अपने यूरोप दौरे के अगले चरण के लिए रवाना होंगे। इस दौरान भारत और यूएई के बीच एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े दो महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

- **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए भारत की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।**
- **पीएम मोदी के विमान को यूएई के हवाई क्षेत्र में एफ-16 लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा एस्कॉर्ट दिया, जबकि अबू धाबी पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।**

CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी हमला करने वाले परजीवी बढ़ रहे हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे "परजीवी" बढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया और सूचना के अधिकार (RTI) का इस्तेमाल कर हर किसी पर हमला करने लगते हैं।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ एक ऐसे वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील संजय दुबे को फटकार लगाई।समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अदालत ने कहा, "दुनिया में कई लोग वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के योग्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं।"सुनवाई के दौरान CJI ने यह भी कहा कि यदि दिल्ली हाईकोर्ट संबंधित वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर देगा। उन्होंने याचिकाकर्ता के फेसबुक पोस्ट और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई भाषा पर भी नाराजगी जताई। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश ने समाज में बढ़ते सोशल मीडिया एक्टिविज्म और आरटीआई के दुरुपयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा, "समाज में पहले से ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते रहते हैं और आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "कई युवा ऐसे हैं जो तिलचट्टों की तरह हर जगह दिखाई देते हैं। उन्हें न रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई स्थान। कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।"

परिसर को माना मां वाग्देवी का मंदिर

भोजशाला पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए इसे देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है। अदालत ने कहा कि इस स्थल पर हिंदू पूजा की परंपरा लगातार जारी रही और समय के साथ यह कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।न्यायालय ने अपने फैसले में माना कि ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक प्रमाणों और स्थापत्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि राजा भोज के समय भोजशाला संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी और वहां मां सरस्वती का मंदिर स्थापित था।हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय से देवी वाग्देवी की प्रतिमा भारत वापस लाने पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के लिए धार में किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि भोजशाला परिसर का प्रबंधन और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास ही रहेगा। ASI ही परिसर की देखरेख और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाएगा। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने ASI के सात अप्रैल 2003 के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने परिसर को राजा भोज से जुड़ा माना और देवी वाग्देवी की प्रतिमा को भारत लाने के मुद्दे पर भी सरकार को विचार करने को कहा है।विष्णु शंकर जैन के अनुसार, अदालत ने मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर भी सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब परिसर में केवल हिंदू पूजा होगी और पूर्व में दी गई नमाज की अनुमति समाप्त मानी जाएगी।

ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी पर TMC का BJP पर हमला

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भाजपा चुनावी वादों से पीछे हट रही है और जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं।तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए भाजपा नेतृत्व, खासकर सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। पार्टी ने लिखा, "क्या हुआ, तेरा वादा? यह बेहद हास्यास्पद है कि सुवेंदु अधिकारी अब बंगाल की जनता से किए गए अपने वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं। क्या अब जवाबदेही तय करने का समय नहीं आ गया है?"TMC ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों को भी मुद्दा बनाया और दिल्ली व कोलकाता के दामों की तुलना करते हुए भाजपा के शासन मॉडल पर सवाल उठाए। पार्टी के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 108.74 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल दिल्ली में 90.67 रुपये और कोलकाता में 95.13 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इन बढ़ती कीमतों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "डबल इंजन नहीं, डबल जुमला सरकार।"दरअसल, शुक्रवार को देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया।

आरजी कर केस में बड़ा एक्शन: तीन IPS अधिकारी निलंबित

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मामले में कथित लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखोपाध्याय के नाम शामिल हैं। नबन्ना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को रिश्वत देने की कोशिश की और बिना लिखित अनुमति के प्रेस वार्ता आयोजित की थी।गौरतलब है कि अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। डॉक्टरों, छात्रों और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। मामले में सबूतों से छेड़छाड़, पुलिस की धीमी जांच और संस्थागत लापरवाही के आरोपों ने लोगों इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। भाजपा ने पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनिहाटी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी तीर्थंकर घोष को 28,836 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। आरजी कर पीड़िता को न्याय दिलाना भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था। का गुस्सा और बढ़ा दिया था। बढ़ते दबाव और अदालत के हस्तक्षेप के बाद जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। इधर, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला करते हुए नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भले ही वे नंदीग्राम सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा।

रथिंद्र बोस बने पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष

पश्चिम बंगाल विधानसभा को शुक्रवार को नया अध्यक्ष मिल गया। कूचबिहार दक्षिण सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रथिंद्र बोस को 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा की परंपरा निभाते हुए रथिंद्र बोस को अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया।मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को ही रथिंद्र बोस के नाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि कूचबिहार दक्षिण से भाजपा विधायक रथिंद्र बोस को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और उम्मीद है कि सभी दल उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे।सुवेंदु अधिकारी ने बोस के अनुभव और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता होने के साथ-साथ पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। उनके पास प्रशासनिक समझ और संगठनात्मक अनुभव दोनों मौजूद हैं, जो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने में मदद करेगा।मुख्यमंत्री ने कहा, "रथिंद्र बोस ने कभी किसी पद के लिए आवेदन नहीं किया। पार्टी ने उनके समर्पण और कार्यशैली को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है। हमें उम्मीद है कि सभी दल उनके नेतृत्व में सदन की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करेंगे।" उन्होंने विपक्षी दलों से भी विधानसभा की पुरानी परंपरा को कायम रखने की अपील की। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर सर्वसम्मति से होता आया है और उम्मीद है कि विपक्ष भी इस लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करेगा।रथिंद्र बोस ने हालिया विधानसभा चुनाव में कूचबिहार दक्षिण सीट पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार अविजित दे भौमिक को 23,284 वोटों के अंतर से हराया था। वे भाजपा विधायक तापस रॉय की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी।

ब्रिक्स सम्मेलन

मिडिल ईस्ट तनाव और वैश्विक सुरक्षा पर मंथन

भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई।एस. जयशंकर और अब्बास अराघची की मुलाकात को ईरान-इज़रायल तनाव के बाद अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है।सम्मेलन में भारत ने संवाद और कूटनीति पर जोर दिया, जबकि ईरान ने अमेरिका और इज़रायल पर अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघन के आरोप लगाए।

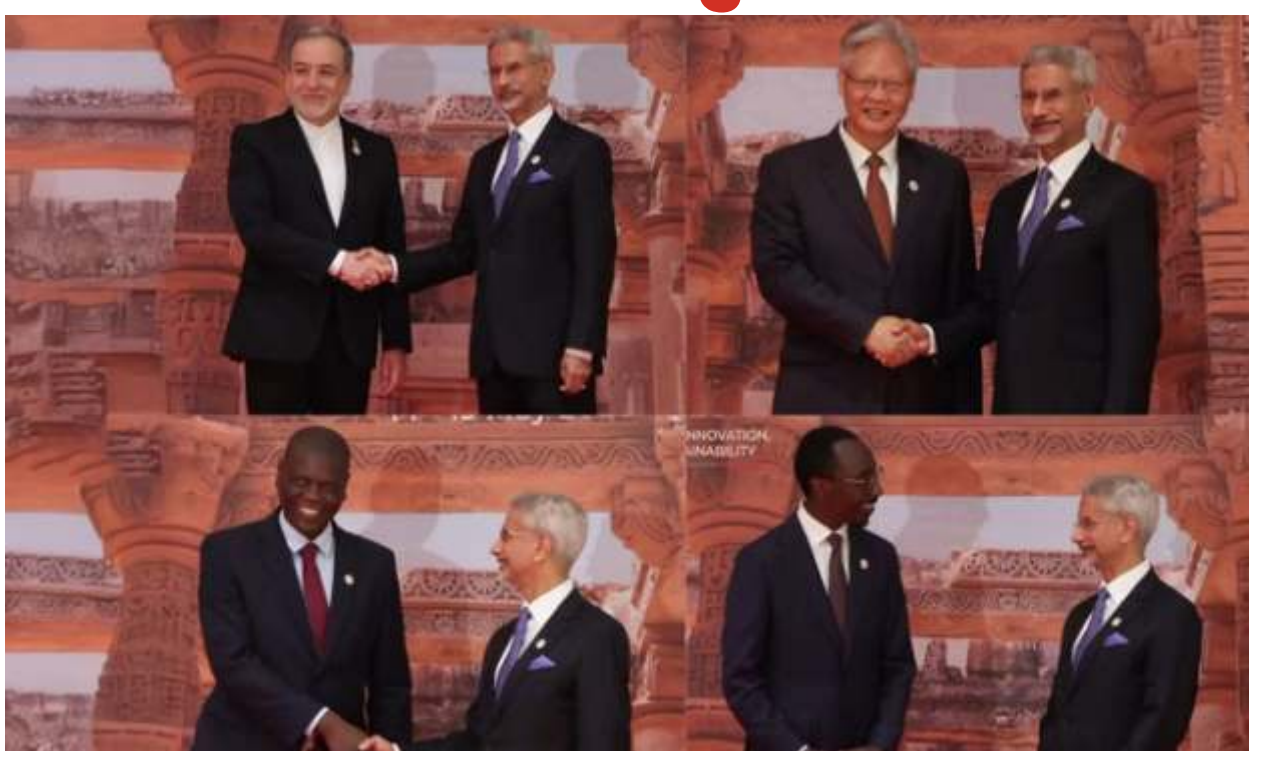

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत (India) में ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों के लिए दो दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। 14 और 15 मई को आयोजित इस सम्मेलन पर दुनियाभर की नज़रें हैं। दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में आज भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने ईरान (Iran) के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) से मुलाकात की। ईरान के खिलाफ युद्ध के बाद यह अराघची का यह पहला भारत दौरा है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर अराघची के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "आज सुबह दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से विस्तृत बातचीत हुई। उनके साथ मिडिल ईस्ट की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा हुई। साथ ही आपसी हित के द्विपक्षीय संबंधों पर भी विचार-विमर्श किया। ब्रिक्स इंडिया 2026 में उनकी भागीदारी के लिए आभार।" विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को मिडिल ईस्ट के नाजुक सुरक्षा माहौल पर बात करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार तनाव, साथ ही समुद्री मार्गों और ऊर्जा अवसंरचना पर मंडरा रहे खतरे वैश्विक चिंता का विषय बने हुए हैं। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, "मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार तनाव, समुद्री यातायात पर खतरे और ऊर्जा अवसंरचना में व्यवधान स्थिति की नाजुकता को उजागर करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर सहित अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध समुद्री प्रवाह वैश्विक आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।" जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। उन्होंने कहा, "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार बना रहना चाहिए। संवाद और कूटनीति ही संघर्षों के समाधान के एकमात्र स्थायी साधन हैं और भारत भी इसका समर्थन करता है।" गुरुवार को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अपने संबोधन में अराघची ने अमेरिका (United States of America) और इज़रायल (Israel) की निंदा की। साथ ही वैश्विक समुदाय से अमेरिका और इज़रायल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने और युद्ध भड़काने के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने वालों की दण्डमुक्ति का अंत हो सके।

पश्चिम एशिया तनाव दोनों देशों के बीच तीखी बहस हुई

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और मौजूदा समय में भारत के अंदर ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई जिसमें हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। लेकिन विदेश मंत्रियों की इस बैठक में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। जहां पर भारत के सामने ही ईरान और यूएई के प्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हमलों को लेकर दोनों देशों के बीच ऐसी तीखी बहस हुई कि बैठक का माहौल पूरी तरीके से गमा गया। दरअसल ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान यूएई की तरफ से ईरान पर पड़ोसी देशों और ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने के आरोप लगाए गए। यूएई के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि ईरान इलाके में अस्थिरता बढ़ा रहा है और उसके कदम पूरे गल्फ इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया। जिसमें उन्होंने इस मुलाकात के दौरान उनके यानी ईरान के डिपुटी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर काजिम गरीबादी के इस बैठक में दिए गए जवाब को साझा किया गया है। जिसमें उन्होंने यूएई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान ने साझा किए बयान में बताया कि यूएई खुद अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद कर रहा है और उसकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य कारही के लिए किया गया। ईरान ने यहां तक दावा किया कि यूएई सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि अग्रेसर यानी हमले में शामिल देश है।

नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा की नई तारीख का एलान

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने नीट-यूजी की नई तारीख का एलान कर दिया है। अब यह परीक्षा देशभर में 21 जून को होगी। इससे पहले यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। हालांकि, पेपर लीक की आशंका के चलते यह सवालों के घेरे में आ गई थी। अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए ने कहा था कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का एलान कर दिया जाएगा। इसके लिए छात्र-छात्राओं को दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं होगी। इस परीक्षा के जरिए मेडिकल में प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा की तारीख की घोषणा करते हुए एनटीए ने कहा कि उसने केंद्र सरकार की अनुमति के बाद नीट-यूजी-2026 की पुन: परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षार्थियों व अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें। इससे पहले, गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नीट-यूजी परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने के मुद्दे पर पहली उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इस अहम बैठक में शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा कराने वाली एजेंसी के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। इस मीटिंग का मकसद यही था कि रद्द हुई परीक्षा को अब नए सिरे से कैसे कराया जाए ताकि आगे कोई भी गड़बड़ी न हो। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बार दोबारा परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन-रात मेहनत करने वाले छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो। गुरुवार को एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह ने भरोसा दिया था कि बच्चों की मेहनत से इस बार कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पेपर लीक माफिया के कारण ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों को नुकसान पहुंचा है। भविष्य में दोबारा ऐसा न हो, उसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे। सिंह ने कहा, जिस भी छात्र या अभिभावक के पास पेपर लीक से जुड़ी जानकारी या सैंपल पेपर उपलब्ध होने से जुड़ी जानकारियां हैं, वे उन्हें ईमेल से भेज सकते हैं। उनका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा।

राहुल के विदेश दौरों पर केंद्रीय मंत्री ने उठाया सवाल

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के यात्राओं पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बिना सूचना दिए विदेश यात्रा करना गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सांसद को अपनी यात्रा के बारे में 3 सप्ताह पहले सूचना देना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'राहुल गांधी की बिना सूचना के विदेश यात्रा गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रत्येक सांसद को अपनी विदेश यात्रा से 3 सप्ताह पहले लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को सूचित करना अनिवार्य है। यह अनुमति नहीं बल्कि सूचना है। सांसद विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सूचना देना आवश्यक है। अगर कोई सांसद विदेश में आतिथ्य सत्कार स्वीकार करता है, तो उसे आमंत्रित करने वाली एजेंसियों या संगठनों द्वारा वहन किया जाने वाला खर्च एफसीआरए के अंतर्गत आएगा। राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं और उनकी 54 विदेश यात्राएं दर्ज की गई हैं। यह केवल 54 यात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वे भारत से बाहर कितने दिन रहे और उन्होंने कितना खर्च किया। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा 'राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुरोध है कि वह नियमों का पालन करें और अधिकारियों को आवश्यक जानकारी दें। उन्हें प्रस्तावित विदेश यात्रा से 3 सप्ताह पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होगा। अगर उन्हें विदेश में आतिथ्य सत्कार स्वीकार करना है, तो उन्हें एफसीआरए के तहत गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा। इसलिए, मैं राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं कि वे स्पष्ट करें कि उन्होंने इतनी विदेश यात्राएं क्यों की हैं।' उन्होंने आगे कहा 'यात्रा करना उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि उन्हें किसने आमंत्रित किया है। भारत के बाहर की एजेंसियों/संगठनों ने उनके नाम पर क्या खर्च किए है? मेरा मानना है कि हर भारतीय को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। खासकर सांसदों को।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर तीखा हमला

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया और जनता के कल्याण के लिए दृढ़ रुख अपनाया। X पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गलतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और दावा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, जिसे उन्होंने वसूली करार दिया, किश्तों में की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की गलती, जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ₹3 का झटका पहले ही लग चुका है। बाकी की वसूली किश्तों में की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि ईंधन संकट के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में नेतृत्व का संकट तथा दूरदर्शी सोच का अभाव है। खरगे ने कहा, जनता को यह समझना होगा कि इस समय अंतरराष्ट्रीय ईंधन संकट के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में नेतृत्व का संकट तथा दूरदर्शी सोच का अभाव है और अक्षमता कूट-कूट कर भरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की गलती, जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ₹3 का झटका पहले ही लग चुका है। बाकी की वसूली किश्तों में की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि ईंधन संकट के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में नेतृत्व का संकट तथा दूरदर्शी सोच का अभाव है। खरगे ने कहा, जनता को यह समझना होगा कि इस समय अंतरराष्ट्रीय ईंधन संकट के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में नेतृत्व का संकट तथा दूरदर्शी सोच का अभाव है और एक्समता कूट-कूट कर भरी है। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, वर्षों तक जब अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें कम थीं या गिर रही थीं, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार यह मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और गैस, पेट्रोल तथा डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को लूटा गया।

संपादक की कलम से

लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित व्यवस्था नहीं है। इसकी असली ताकत जनता के उस भरोसे में छिपी होती है कि उसका मत स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी है। जब चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तब मामला केवल किसी दल की जीत या हार का नहीं रहता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी बहस के केंद्र में आ जाती है। हाल के दिनों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे आरोपों ने इसी चिंता को फिर सामने ला दिया है। यह कहा जा रहा है कि कई बार केवल कुछ सीटों का परिणाम ही नहीं, बल्कि पूरी सत्ता का स्वरूप भी चुनावी प्रक्रियाओं से प्रभावित हो सकता है। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी, मतदान के दौरान कथित अनियमितताएं और संस्थागत निष्पक्षता पर उठते सवाल लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत हैं। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि उसका मत पूरी ईमानदारी से दर्ज नहीं हो रहा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर पड़ने लगती है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग माना जाता है। करोड़ों मतदाता हर चुनाव में उत्साह से भाग लेते हैं और इसी भागीदारी से लोकतंत्र को शक्ति मिलती है। लेकिन यही शक्ति तब कमज़ोर होने लगती है जब चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होता है। संदेह चाहे वास्तविक हो या केवल राजनीतिक विवाद का हिस्सा, उसका असर आम नागरिक के मन पर पड़ता है। मतदाता के मन में यदि यह सवाल पैदा हो जाए कि उसका मत सही अर्थों में गिना भी जाएगा या नहीं, तो यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर मानी जाएगी।यह भी सच है कि चुनावी हार के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से यह प्रवृत्ति देखी जाती रही है कि जब परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आते, तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन लोकतंत्र में केवल आरोप पर्याप्त नहीं होते। यदि किसी को चुनावी अनियमितताओं पर संदेह है, तो उसके समर्थन में प्रमाण और तथ्य भी सामने आने चाहिए। बिना ठोस आधार के लगाए गए आरोप केवल राजनीतिक वातावरण को और अधिक अविश्वास से भरते हैं। दूसरी ओर, चुनाव कराने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं, बल्कि जनता के सामने निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है। मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया, मतगणना और परिणामों की घोषणा तक हर स्तर पर अधिक पारदर्शिता समय की मांग है। यदि कहीं भी शंका की गुंजाइश रह जाती है, तो उसे दूर करने के लिए संस्थाओं को तत्परता से सामने आना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है। यह विश्वास टूटने लगे तो चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखा जाए। लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब आम नागरिक को यह भरोसा होगा कि उसका मत किसी भी परिस्थिति में उसकी आवाज़ बनकर सामने आएगा। यही भरोसा लोकतंत्र की असली नींव है और इसकी रक्षा करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

नीट यूजी दोबारा होगा
पेपर लीक पर सरकार की सख्ती

पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने नीट यूजी परीक्षा रद्द कर नई तारीख घोषित कर दी है।धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।सरकार ने छात्रों पर आर्थिक बोझ न डालने, अतिरिक्त समय देने और अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित कराने का भी ऐलान किया है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि NTA ने नीट UG की नई तारीख का ऐलान किया है। 3 मई को इसकी परीक्षा हुई, 7 मई को पता चला गेस पेपर मे कुछ सिमिलर कनेक्शन है। इसके बाद 2-3 दिन में ये साफ हो गया कि गेस पेपर के माध्यम से क्वेश्चन लीक किए गए हैं। हमने तुरंत चर्चा करके जांच एजेंसियों को मामला सौंपा और राज्यों की एजेंसियों से भी संपर्क किया। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द कर दिया। हम अपना दायित्व मानते हैं और समाधान के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम आज नई तारीख के साथ आए हैं। आज से करीब एक महीने के बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। हमारी अप्रोच इस बार भी जीरो टॉलरेंस की होगी। हमारी लड़ाई परीक्षा माफियाओं के साथ है। विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जा रहा है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सरकार ने तुरंत सीबीआई को जांच सौंपी। इस बार सीबीआई मामले की तह तक जाएगी। कहां चूक हुई है, उसे एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं, अगले एग्जाम में वह इससे दूर रहें नहीं तो उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम इस घटना से बहुत दुखी हैं, लेकिन एक बड़े उद्देश्य को देखते हुए हमें यह कठोर निर्णय लेना पड़ा, ताकि छात्रों के साथ अन्याय न हो सके। मैं छात्रों से कहूंगा कि वह बिना भय के एग्जाम दें। एनटीए में जीरो-एरर हो यह हमारा दायित्व है और हम यह करके रहेंगे। एनटीए हर साल एक करोड़ बच्चों का एग्जाम कराती है। विद्यार्थियों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े उसका हम दायित्व लेते हैं। दोबारा एग्जाम की कोई फीस नहीं ली जाएगी। एनटीए ने तय किया है कि हम विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अपने पसंद का शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय देंगे। वहीं परीक्षा से जुड़े बड़े ऐलान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में होने वाली फॉर्मेलिटीज की वजह से समय बेकार होता है, इसके लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दोबारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को दोपहर 2 बजे से 5.15 बजे तक का समय दिया जाएगा। सभी के पास 14 जून तक एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे कि इस बार नीट की परीक्षा के समय विद्यार्थियों के आवागमन के बोझ को कम किया जा सके। वहीं मौसम खराब रहने पर क्या करेंगे इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। छात्र किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। राधाकृष्णन कमेटी का पूरा पालन करने के बाद भी इसमें चूक हुई है, इसमें सुधार की हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगले साल से नीट की परीक्षा कम्प्यूटर से होगी।

मायावती ने राजकुमार भाटी की अपमानजनक टिप्पणियों की आलोचना की

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे ने व्यापक आक्रोश पैदा किया है और एसपी नेतृत्व से इसे गंभीरता से लेने का आग्रह किया। X पर एक पोस्ट में मायावती ने इन टिप्पणियों को अशोभनीय, और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इनसे ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मायावती ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी (एसपी) के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मण समुदाय के बारे में हाल ही में की गई अशोभनीय, अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियों और बयानों ने स्वाभाविक रूप से व्यापक आक्रोश और कड़ी निंदा को जन्म दिया है। इस विवाद के परिणामस्वरूप पुलिस मामला दर्ज होने के बावजूद, मामला शांत होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। हालांकि, एसपी नेतृत्व की संकीर्ण जाति-आधारित राजनीति को देखते हुए इस मुद्दे पर चुप्पी ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है और इसे काफी हद तक बढ़ने दिया है। स्थिति भी लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है। मायावती ने आगे जोर देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में, सपा प्रवक्ता के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से ब्राह्मण समुदाय की गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सपा प्रमुख को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए, ब्राह्मण समुदाय से माफी मांगनी चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए – यही उचित कार्रवाई होगी। बसपा संगठन की नेता ने यह भी कहा कि इस विवाद से सपा की जातिवादी रणनीति और चरित्र उजागर होता है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बसपा ने हमेशा ब्राह्मणों, दलितों, अति पिछड़े वर्गों और मुसलमानों सहित सभी समुदायों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यह ताजा घटनाक्रम जनता की नजर में यह भी साबित करता है कि सपा की जातिवादी रणनीति और चरित्र – विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय के प्रति उसका विरोध, ठीक उसी तरह जैसे दलितों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदायों के प्रति उसका रवैया – नहीं बदला है; बल्कि, यह और भी गहरा गया है।

बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
15 आईएएस अधिकारियों के तबादले

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बिहार में जब से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है लगातार बेहतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में एक बार फिर राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. शुक्रवार (15 मई, 2026) को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. ट्रांसफरकी लिस्ट में कुल 15 आईएएस अधिकारियों का नाम है. कई विभागों के सचिव और अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं. सेंथिल कुमार श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं. वे पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के भी अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे. वहीं प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इनके अलावा पंकज पाल पथ निर्माण विभाग के सचिव बनाए गए हैं. एके सिंह सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव बने हैं. गन्ना उद्योग विभाग की बात की जाए तो धर्मेंद कुमार सिंह सचिव बने हैं. दीपक आनंद खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव बनाए गए हैं. दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. वे सचिव के तौर पर शिक्षा और खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे. अवनीश कुमार सिंह खान एवं भूत्तव विभाग के सचिव बनाए गए हैं. हिमांशु शर्मा को विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार को पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त का प्रभार दिया गया है. बिहार में हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को राज्य सरकार की नई कार्यशैली और विकास योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार आगामी महीनों में प्रशासनिक कामकाज को और तेज करने के लिए अनुभवी अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दे रही है। शिक्षा, तकनीकी विकास, सड़क निर्माण, खाद्य आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए सचिवों की नियुक्ति से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रमंडलीय स्तर पर भी अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर प्रशासनिक निगरानी मजबूत करने की कोशिश की गई है। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को समय पर पूरा कर जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना बताया जा रहा है।

सिर्फ SAT-GRE काफी नहीं

अमेरिका में एडमिशन की नई कुंजी बना कैपस्टोन प्रोजेक्ट

12वीं के बाद अधिकांश छात्रों का सपना होता है कि वे विदेश में पढ़ाई करें और खासकर अमेरिका जैसे देश में जाकर अपना करियर बनाएं. लेकिन यह सपना सिर्फ अच्छे मार्क्स से पूरा नहीं होता. इसके लिए SAT, ACT (यूजी के लिए), GRE या GMAT (पीजी के लिए) और अंग्रेजी दक्षता के लिए IELTS या TOEFL जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं. हालांकि, अब सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही काफी नहीं है,क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऐसे छात्रों को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी हों. और इसी में सबसे अहम भूमिका निभाता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जो उनकी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करता है. ऐसे में अगर आप भी अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं या बैचलर्स/मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए. इसे समझना जरूरी है क्योंकि यह आपकी पढ़ाई की प्लानिंग, प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाने और ग्रेजुएशन के बाद करियर बनाने में काफी मदद करता है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं. कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक ऐसा अकादमिक प्रोजेक्ट होता है, जो किसी कोर्स के अंत में कराया जाता है, जहां एग्जाम के जरिए सिर्फ कोर्स से जुड़ी जानकारी को परखा जाता है और इसका उद्देश्य छात्र की पूरी सीख को एक साथ परखना होता है. यह प्रोजेक्ट यह दिखाता है कि छात्र ने अपने विषय को कितनी गहराई से समझा है और वह उसे वास्तविक जीवन में कैसे लागू कर सकता है. यह प्रोजेक्ट यूजी और पीजी दोनों स्तरों पर अहम होता है. आसान शब्दों में कहें तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट हर डिग्री के लिए जरूरी होता है. यह एक सेमेस्टर या पूरे साल चलने वाला प्रोजेक्ट होता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट केवल थ्योरी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें रिसर्च, प्रैक्टिकल वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल होती है. यानी छात्र को किसी वास्तविक समस्या पर काम करना होता है और उसका समाधान तैयार करना होता है. कैपस्टोन प्रोजेक्ट के कई प्रकार होते हैं. इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, बिजनेस प्लान, डिजाइन प्रोटोटाइप, केस स्टडी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग के छात्र कोई मशीन या सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, जबकि मैनेजमेंट के छात्र बिजनेस केस स्टडी पर काम करते हैं. वहीं आर्ट्स या मीडिया के छात्र डॉक्यूमेंट्री, फिल्म या कंटेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं. वही प्रोजेक्ट का टाइप चाहे जो भी हो, इसका मुख्य लक्ष्य एक ही रहता है: यह साबित करना कि स्टूडेंट गंभीर रूप से सोच सकता है, जटिल समस्याओं को हल कर सकता है और अपनी फील्ड में प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है. अमेरिका की यूनिवर्सिटीज कैपस्टोन प्रोजेक्ट को खास महत्व देती हैं, क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली में प्रैक्टिकल लर्निंग को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रोजेक्ट छात्रों के पोर्टफोलियो का मजबूत हिस्सा बनता है और एडमिशन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. इससे यूनिवर्सिटी को यह समझने में मदद मिलती है कि छात्र सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, बल्कि वह अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करने की क्षमता भी रखता है. कैपस्टोन प्रोजेक्ट का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है. इसमें टीमवर्क, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन जैसी स्किल्स विकसित होती हैं. यही स्किल्स आगे चलकर नौकरी पाने में मदद करती हैं. कई बार कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखकर ही छात्रों को इंटर्नशिप या जॉब ऑफर कर देती हैं. वही अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि केवल एग्जाम पास करना ही काफी नहीं है. एक मजबूत कैपस्टोन प्रोजेक्ट आपकी प्रोफाइल को अलग बनाता है और एडमिशन के मौके बढ़ा देता है.

महाराष्ट्र बोर्ड: कुल 92.09 प्रतिशत छात्र-छात्राएं परीक्षा में सफल रहे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज, 8 मई 2026 को कक्षा 10वीं (SSC) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना परिणाम सीट नंबर और माता के पहले नाम की सहायता से देख सकते हैं। छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट और मार्कशीट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in और sscresult.mahahsscboard.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। बोर्ड अध्यक्ष Trigun Kulkarni के अनुसार, इस बार भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.96% रहा, जबकि लड़कों का कुल पास प्रतिशत 89.56% दर्ज किया गया। रिजल्ट में कोंकण मंडल ने 97.62% पास प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं छत्रपति संभाजीनगर मंडल 88.41% के साथ सबसे नीचे रहा। इसके अलावा मुंबई का रिजल्ट 94.97%, पुणे 94.24%, कोल्हापुर 95.47%, अमरावती 90.50%, नासिक 90.53% और लातूर 88.42% दर्ज किया गया। महाराष्ट्र कक्षा 10वीं के परिणाम छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट ही नहीं, बल्कि अन्य वैकल्पिक माध्यमों से भी देख सकते हैं। विद्यार्थी sscresult.mkcl.org, mahahsscboard.in और results.gov.in जैसी वेबसाइटों पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉकर और एसएमएस सेवा के माध्यम से भी स्कोरकार्ड प्राप्त किया जा सकता है। जो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उन्हें पहले उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी लेना जरूरी होगा। फोटोकॉपी मिलने की तारीख से पांच कार्यदिवस के भीतर छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट Maha HSSC Board पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा करके करना होगा।

ODI World Cup 2027

नामीबिया पर बाहर होने का खतरा

27 वनडे विश्व कप में खेलने को लेकर बड़ा बयान

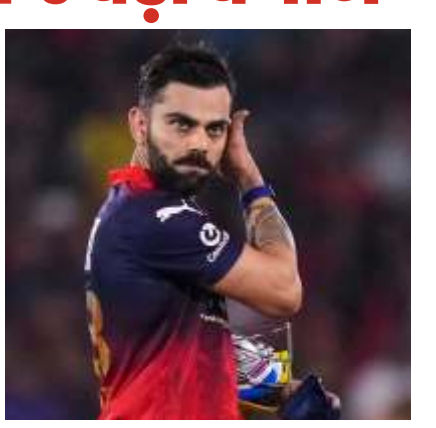

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए विराट कोहली ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर और 2027 वनडे विश्व कप को लेकर खुलकर बात की। विराट ने कहा, 'मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। अगर मैं जिस माहौल का हिस्सा हूं उसमें वैल्यू जोड़ सकता हूं और उस माहौल को भी लगता है कि मैं योगदान दे सकता हूं, तो मैं खेलता रहूंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा महसूस कराया जाए कि मुझे अपनी कीमत और अहमियत साबित करनी है, तो मैं उस जगह पर नहीं रहना चाहता।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपनी तैयारी के साथ पूरी तरह ईमानदार हूं। मैं जिस तरह खेल को अपनाता हूं, उसमें पूरी मेहनत करता हूं। भगवान ने मुझे मेरे क्रिकेट करियर में बहुत कुछ दिया है और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा।' विराट का यह बयान उन चर्चाओं को तूल दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा था कि टीम इंडिया में सबकुछ ठीक नहीं है। पिछले साल रोहित शर्मा और उसके बाद विराट कोहली ने अचानक टेस्ट से संन्यास की घोषणा की थी। दोनों अब सिर्फ वनडे खेलते हैं और कई बार यह बात सामने आई कि दोनों का 2027 के वनडे विश्वकप में हिस्सा लेना भी तय नहीं है। ऐसा कहा गया था कि दोनों ने बीसीसीआई से ये कहा है कि वह खेलने को लेकर कमिटेड नहीं हैं। फिर कोच गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच सबकुछ ठीन नहीं होने की रिपोर्ट्स भी आई थीं। हालांकि, तीनों ने कभी खुलकर इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन इस विवाद ने काफी तूल पकड़ी थी। रोहित को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अचानक कप्तानी से हटा दिया गया था।

चौथी पसंद के स्ट्राइकर

एमबाप्पे और कोच अल्वारो अर्बेलोआ के बीच मतभेद

काइलिन एमबाप्पे गुरुवार को रियाल मैड्रिड के ओविएडो के खिलाफ स्पेनिश लीग फुटबॉल मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह न मिलने के बाद कहा कि कोच अल्वारो अर्बेलोआ ने उनसे कहा कि वह टीम के चौथी पसंद के स्ट्राइकर हैं। अर्बेलोआ ने हालांकि एमबाप्पे की बात पर हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की थी और वह नहीं जानते कि फ्रांस के इस फुटबॉलर को ऐसा क्यों लग रहा है। एमबाप्पे बाएं पांव में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव से परेशान थे लेकिन उन्होंने कहा कि वह ओविएडो के खिलाफ शुरु से खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन अर्बेलोआ ने उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा, "मैं पूरी तरह से फिट हूं लेकिन मैं इसलिए नहीं खेला क्योंकि कोच ने मुझसे कहा कि मैं टीम में (फ्रेंको) मास्टांटुओनो, विनी (विनीसियस जूनियर) और गोंज़ालो (गार्सिया) के बाद चौथी पसंद का स्ट्राइकर हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं।" एमबाप्पे ने कहा, "मैं शुरुआती लाइनअप में खेलने के लिए तैयार था, यह उनका फैसला था। आप कोच से नाराज़ नहीं हो सकते, आपको हमेशा कोच की राय का सम्मान करना चाहिए। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा और शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने का इंतज़ार करूंगा।" अर्बेलोआ ने बाद में कहा कि उन्होंने एमबाप्पे से कभी नहीं कहा कि वह टीम में चौथी पसंद के स्ट्राइकर हैं। उन्होंने कहा, "मेरे पास चार स्ट्राइकर नहीं हैं और मैंने एमबाप्पे को ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि वह मेरी बात को सही तरह से नहीं समझ पाए। मैं उन्हें कभी यह नहीं कह सकता कि वह चौथी पसंद के स्ट्राइकर हैं।

'अंधेरा' कमेंट पर विवाद, मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा के अंदाज में दिया जवाब

अर्शदीप सिंह आज की तारीख में चर्चा में हैं। वैसे तो अभी आईपीएल चल रहा है और यहां खेल रहे सभी खिलाड़ी किसी ना किसी बात को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। वैसे तो प्लेयर की अपने अच्छे खेल के लिए बात होनी चाहिए, लेकिन अर्शदीप सिंह का मामला कुछ और है। पहले तो उन्होंने तिलक वर्मा को लेकर ऐसी बात की, जो शोभा नहीं देती, इसके बाद अब वे फैंस पर भी बरस रहे हैं। इस बीच मुंबई इंडियंस ने उनका जवाब दिया है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आईपीएल में गुरुवार को मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया। पंजाब के लिए ये मैच काफी अहम था, लेकिन मुंबई ने उसे चारोखाने चित्त कर दिया। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जो तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह का है। अर्शदीप सिंह तिलक को अंधेरा कहकर पुकारते हैं। तिलक बड़ी तमीज से उनसे ये कहने के लिए मना करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अर्शदीप अपनी बात में कोई सुधार नहीं करते हैं। अर्शदीप ने जो कुछ भी कहा है, उसे लोग नस्लीय टिप्पणी कह रहे हैं। इस बीच इसका वीडियो सोशल मीडिया जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। ये पता नहीं है कि ये वीडियो कब का है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसे अर्शदीप सिंह ने खुद ही रिकॉर्ड किया है। इस बीच अर्शदीप सिंह एक फैन से भी भिड़ गए। एक फैन ने अर्शदीप से कहा कि IPL से पंजाब का नाम हटा दो, तुम हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। इस पर अर्शदीप सिंह ने लिखा है कि सिंह साहब, आपने पंजाब के लिए कौन सा तीर मार लिया है? अब, जो लोग अपने परिवार से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगते हैं, वे हमें सलाह देंगे कि पंजाब का नाम रखना है या नहीं? इसको लेकर भी अर्शदीप की लगातार आलोचना हो रही है। मुंबई इंडियंस ने अर्शदीप के अंधरे वाले कमेंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जो एक गाना है। इस बीच आपको याद होगा कि जब मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को मैच हरा दिया, तब तिलक वर्मा ने अपनी शर्ट उठाकर दिखाया था। पहले तो लोग इसका मतलब नहीं समझे, लेकिन बाद में पता चला कि अर्शदीप ने जो अंधेरे वाला कमेंट किया था, वो उसका जवाब था। तिलक ने अपनी टीम के लिए एक मैचविनिंग पारी खेली।

घोंघों की रेस ने खींचा दुनिया का ध्यान

स्लो लाइफ को सेलिब्रेट करता है ताइवानी शहर

दुनिया जहां तेज भागदौड़ से भरी है, वहीं कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. आखिर इतनी भागदौड़ क्यों? क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ तेजी है? क्या कुछ काम धीरे नहीं हो सकते? इसी सोच और फिलॉसफी पर ताइवान के हुलिएन काउंटी में बसा छोटा सा शहर फेंगलिन चलता है. इस शहर में लोग तेज रफ्तार जिंदगी नहीं, बल्कि धीमी और संतुलित जीवनशैली को सेलिब्रेट करते हैं. यही वजह है कि यहां आयोजित

होने वाली अनोखी घोंघा रेस अब पूरे ताइवान में चर्चा का विषय बन गई है. घोंघा, जिसकी रफ्तार बेहद धीमी होती है, यहां की पहचान बन चुका है. ⊙

पहले ही हो गई थी CM बनने की भविष्यवाणी

विजय की कार का नंबर वायरल!

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में इस बार विजय थलापति का जादू सिर चढ़कर बोला. उनकी पार्टी का प्रदर्शन ऐसा रहा कि अच्छे- अच्छे दिग्गज चित हो गए.

मुख्यधारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हर तरफ विजय का ही जलवा है. ऐसे में इंटरनेट पर उनकी जीत से जोड़कर विजय के कई पुराने- नए फिल्मों के क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं. इनमें से सबसे खास वीडियो क्लिप उनकी GOAT आम की फिल्म का है. इस फिल्म का वायरल हो रहा क्लिप क्यों

खास है, वह इसे देखकर पता चल जाएगा. विजय की 2024 में आई फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम GOAT' के इस वीडियो क्लिप में विजय एक कार पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. उस कार का नंबर है - 'TN 07 CM 2026'. वैसे तो यह वीडियो तब से वायरल है, जब उनकी पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू किया था. अब जब उन्होंने चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल की है और उनके सीएम बनना पक्का हो गया है. ⊙

हेल्थ से जुड़ी इन दिक्कतों से उठ रहे सवाल

क्या फैसले लेने में कमजोर पड़ रहे ट्रंप?

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक लग्जरी ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रेन के अंदर की सुविधाएं और हालत दिखाई गई हैं, जिसे देखकर कई लोग हैरानी जता रहे हैं.

ट्रंप की सेहत को लेकर इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं (Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. हाल ही में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप कुछ देर के लिए आंखें बंद किए और सिर झुकाए नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य और मानसिक सतर्कता को लेकर सवाल उठने लगे. यह घटना 11 मई 2026 को 'Moms.gov' वेबसाइट लॉन्च इवेंट के दौरान हुई. वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ट्रंप कार्यक्रम के बीच झपकी लेते दिखाई दिए. हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे सामान्य "ब्लिंकिंग" यानी पलक झपकना बताया और कहा कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप की सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर इस तरह की चर्चा हुई हो. 2025 और 2026 के दौरान कई बैठकों और कार्यक्रमों में भी वह आंखें बंद किए या थके हुए दिखाई दिए थे. इसी वजह से अब उनकी उम्र और कामकाजी क्षमता पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. ट्रंप की सेहत को लेकर इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं. जुलाई 2025 में व्हाइट हाउस ने बताया था कि उनके पैरों में सूजन और हाथों पर निशान "क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी" यानी नसों से जुड़ी समस्या की वजह से थे. ⊙

व्हाइट हाउस खारिज करता रहा है दावा

व्हाइट हाउस लगातार यह कहता रहा है कि ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ हैं. ट्रंप खुद भी कई बार दावा कर चुके हैं कि वह पूरी तरह से फीट हैं और कॉग्निटिव टेस्ट पास कर चुके हैं. उनका कहना है कि वह कम नींद लेकर भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं. कॉग्निटिव टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है. ⊙

शिकार करते हुए शेर का दिखा खौफनाक नजारा

गुजरात के गिर नेशनल पार्क में सफारी पर गए टूरिस्टों की उस वक्त सांसें अटक गईं, जब उनकी आंखों के सामने शेरों ने एक गाय पर जानलेवा हमला बोल दिया. सफारी जिप के बेहद करीब हुए इस शिकार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि टूरिस्ट आराम से सफारी का आनंद ले रहे थे. तभी एक शेरनी धीरे-धीरे जिप के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ती नजर आती है. ⊙

वेलकम टू द जंगल का टीजर रिलीज
30 सितारों की कॉमेडी से भरपूर होगा धमाका

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का आज टीजर रिलीज हो गया है। फैन्स इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। फिल्म में 30 से ज्यादा सितारों को दमदार किरदारों में कास्ट किया गया है और जल्द ही कॉमेडी का पिटारा खुलने वाला है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। बता दें कि फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म होने वाली है। फिल्म में 30 से ज्यादा बड़े सितारों को अहम किरदारों में कास्ट किया गया है। आज रिलीज हुए टीजर में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है। टीजर में अक्षय कुमार का वही पुराना कॉमिक अंदाज देखने को मिला और उनकी टाइमिंग ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। साथ ही अरशद वारसी से लेकर सुनील शेट्टी और दिशा पाटनी तक कई दिग्गज सितारे इस फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड में अब तक हमने कई मल्टीस्टारर फिल्में देखी हैं और उन्हें खूब एंजॉय किया है। अब वेलकम टू द जंगल भी इसी तरह की एक फिल्म जिसमें 30 से ज्यादा धाकड़ एक्टर्स अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार के साथ फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी और परेश रावल ने लीड रोल प्ले किए हैं। इसके साथ ही फिल्म की कहानी के लिए सपोर्टिंग कास्ट को भी कास्ट किया गया है। जिसमें रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी और उर्वशी रौतेला, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक दमदार किरदारों में दिखेंगे। फिल्म को लेकर दर्शक भी काफी उत्साहित हैं और आज रिलीज हुए टीजर ने एक बार फिर इस फिल्म को चर्चा में ला दिया है।

बेमौसम बारिश और आंधी से यूपी में आम की फसल तबाह, बढ़ेंगे दाम

उत्तर प्रदेश में बेमौसम आंधी, बारिश और कीटों के हमले से आम की फसल को 40 से 60 फीसदी तक नुकसान पहुंचा है। मलिहाबाद समेत कई जिलों के किसान भारी नुकसान और बढ़ती लागत से परेशान हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे मौसम परिवर्तन का असर बता रहे हैं। कम उत्पादन के कारण इस बार आम महंगा हो सकता है, हालांकि सरकार और निर्यातक किसानों को राहत देने के प्रयास में जुटे हैं।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

बेमौसम आए आंधी-तूफान और बूंदाबांदी ने आम किसानों को बेजार कर दिया है। प्रदेशभर में करीब 40 से 50 फीसदी आम की फसल को नुकसान हुआ है। एक तरफ किसान सिसक रहे हैं, वहीं कम उत्पादन की बजह से आम का स्वाद महंगा साबित होगा। हालांकि उद्यान विभाग किसानों के दर्द को कम करने की कोशिश में लगा है। मौसम का बदलाव आम के लिए जहर बन गया है। कुछ ऐसी ही बात आसपास के बागवान समौर सिंह, विपिन शंकर शुक्ला आदि भी बताते हैं। मलिहाबाद में बने औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के विशेषज्ञ डॉ. सचिन आर्या कहते हैं कि मौसम ने नुकसान किया। पहले भुनगा फिर थ्रीप्स का अटैक रहा। यह सूक्ष्म कीट बऔर (फूल) और नई पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल का स्प्रे करना होता है। इससे लागत बढ़ गई। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य विशेषज्ञ कृष्ण मोहन चौधरी का कहना है कि फल लगने के बाद जितनी लू चलती है, आग के लिए उतना ही अच्छा होता है। कीट और बीमारियां कम लगती हैं। आम उत्पादकों की समस्या को देखते हुए अन्य राज्यों में आम निर्यात का प्रयास शुरू कर दिया गया है। बागों के बीच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैगिंग कराई जा रही है। कुसमौरा के बाग में मिले विपिन मौर्य ने बताया कि किराये पर बाग लेते हैं। इस बार करीब 70 लाख रुपये खर्च किए हैं। अबकी बार लागत निकलनी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि प्रति बीमा बाग का किराया 45 से 50 हजार। दवा छिड़काव, मजदूरी, बैग बांधने और तोड़ाई आदि का खर्चा 30 से 35 हजार है। कुल खर्चा करीब 80 हजार लगता है। इस बार लागत निकलना मुश्किल है। कहा कि बौर आते ही तूफान आया। रिमझिम फुहारें पड़ीं। रोग लग गया। खराब फलों को हटाकर बचे फल में बैग बंधवा रहे हैं। करीब दस साल से बागों में काम करने वाले मुनऊ बताते हैं कि पांच साल पहले ऐसे ही हालात थे। मलिहाबाद ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर हिस्से में आम की फसल प्रभावित हुई है। बिजनौर में करीब 21 हजार हेक्टेयर में आम के बाग हैं। सहारनपुर के आम कारोबारी हाजी नसीम बताते हैं कि यहां 50 फीसदी फसल खराब हो गई है। यही हालात रहे तो आम खाने को लोग तरस जाएंगे। बागपत में रहौल क्षेत्र में करीब 150 किस्म के 400 एकड़ में आम के बाग हैं। बागान मालिक हबीब चौहान व जुनैद फरीदी ने बताया कि 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है। यही हाल शामली, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर का है। अमरोहा में करीब 40 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है। यूपी मैंगो एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी ने बताया कि दुबई से 250 मीट्रिक टन आम का ऑर्डर मिला है।

- बुंदेलखंड झांसी में करीब 80 हेक्टेयर में करीब 40 से 45 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।
- पूर्वांचल वाराणसी और आसपास के जिलों में आंधी-बारिश से आम की फसल को 60 फीसदी नुकसान की आशंका है। सोनभद्र के किसान संदीप सिंह चंदेल ने बताया कि मार्च की आंधी ने बौर चौपट कर दिया है

माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र में 23213 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र में 23213 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधी भर्ती के खाली पदों का अधियाचन भेजा है। अब आयोग इसकी आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पिछली बार 2016 में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी किंतु यह पूरी 2021 में हुई थी। इस तरह लंबे समय बाद खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई है। विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे अधियाचन के अनुसार प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003, प्रवक्ता के 2705, सहायक अध्यापक (शिक्षक) के 16114 व सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) के 1889 कुल 23213 पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि 4479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधानों व शिक्षकों के सीधी भर्ती के अंतर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अधियाचन भेजा गया है। उन्होंने बताया कि भौतिक रूप से अधियाचन देने के साथ ही ई-पोर्टल पर भी इसकी सूचना भेजी जा रही है। प्रदेश में 4512 एडेड विद्यालय हैं। इनमें 4479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के मिलने से इन विद्यालयों की पठन-पाठन प्रक्रिया को गति मिल सकेगी। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में इन खाली पदों की जगह वर्तमान शिक्षकों से ही पठन-पाठन का काम पूरा कराया जा रहा है। इससे कई बार छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। जो अब नए सत्र में सामान्य हो सकेगा। माध्यमिक के साथ ही प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में भी लंबे समय से शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। इसके लिए समय-समय पर उनके द्वारा धरना-प्रदर्शन भी किया गया है।

लखनऊ में शुक्रवार सुबह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

शुक्रवार सुबह से लखनऊ में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पहले से ही महंगाई और गैस की किल्लत का सामना कर रहे आम आदमी को बढ़े हुए दामों का एक और झटका लगा है। लखनऊ में पेट्रोल का दाम 2 रुपये 84 पैसा और डीजल के दामों में 3.01 रुपये की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आम जनता को अब पेट्रोल 97.55 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 82 पैसा प्रति लीटर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी बढ़ोत्तरी की गई है। लखनऊ में सीएनजी के दाम भी दो रुपये बढ़ाए गए हैं। कहा जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने का ये पहला झटका है। आगे कई बार और दाम बढ़ाए जा सकते हैं। लखनऊ में अभी सीएनजी की कीमत 98 रुपये प्रतिकिलो है। ग्रीन गैस लिमिटेड के एजीएम प्रवीण सिंह ने बताया कि लखनऊ, अयोध्या सुल्तानपुर, उन्नाव और आगरा में सीएनजी के पुराने दाम ही लागू होंगे। हालांकि, सीएनजी के दाम जब रिवाइज हुए थे तभी 2 रुपए बढ़ गए थे। उसके बाद से यही कीमत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। वहीं, प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बृहस्पतिवार को साइकिल से विधानभवन पहुंचे। मंत्री दिनेश प्रता सिंह ई रिक्शा से अपने कार्यस्थल पहुंचे। आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने

वाराणसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सिंगल कार का प्रयोग शुरू किया। महापौर अशोक तिवारी गुरुवार को आवास से पैदल ही नगर निगम कार्यालय पहुंचे। गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने स्कॉर्ट वाहन का इस्तेमाल बंद कर दिया। सांसद रवि किशन ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया। अयोध्या में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयंत कुमार ने अपने सुरक्षा वाहन नगर निगम को वापस कर दिया। बाराबंकी में डीएम ईशान प्रताप सिंह कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल गए।

लखनऊ में 5 साल का टूटा रिकॉर्ड, मई का सबसे ठंडा दिन

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में मंगलवार 5 साल के रिकॉर्ड में मई का सबसे ठंडा दिन बन गया। मंगलवार (5 मई) को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले 2021 में 29 मई को 27.8°C तापमान दर्ज हुई था। दो दिन मौसम सुहाना रहने के बाद आज (बुधवार) सुबह से तेज धूप निकली। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को सामान्य से 11.4 डिग्री कमी के साथ अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम था। सोमवार सुबह 8:30 बजे से मंगलवार की सुबह 8:30 बजे तक 16 mm बारिश हुई। इस दौरान अधिकतम नमी 91% दर्ज हुई। न्यूनतम नमी 66 फीसदी रही। मौसम केंद्र लखनऊ के अधिकारी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, आज लखनऊ के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गरजने के साथ एक-दो बार बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है।

शकुंतला मिश्रा के कुलपति ने साइकिल से जाना शुरू कर दिया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में डॉ.शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने गाड़ी छोड़ दी है। उन्होंने शुक्रवार से ऑफिस साइकिल से जाना शुरू कर दिया है। उनके आवास से ऑफिस करीब दो किलोमीटर है। साइकिल से पहली बार ऑफिस पहुंचने पर उन्होंने कहा कि सभी स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स कम दूरी साइकिल से चलना शुरू करें। कुलपति के अंगरक्षक ने भी उन्हें साइकिल से ही उनका स्कार्ट किया। कुलपति का आवासीय परिसर से प्रशासनिक भवन तक साइकिल से पहुंचने का यह अंदाज परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। रास्ते में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उन्हें साइकिल पर देखकर अभिवादन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह पहल ऊर्जा संरक्षण, फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। कुलपति ने भी कहा कि छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल सबसे बेहतर और पर्यावरण अनुकूल साधन है। इससे न केवल ईंधन की बचत होती है, बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।

सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया

लखनऊ कलेक्ट्रेट में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सपा सांसद माफी मांगो और शर्म करो के नारे लगाए। और सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया और मीडिया प्रभारी चेतना पांडे ने विरोध जताते हुए सांसद को बर्खास्त करने की मांग की। चेतना पांडे ने कहा कि सपा सांसद का बयान पार्टी के चरित्र को दर्शाता है। यह लोग ना तो प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और ना इनके यहां महिलाओं के लिए सम्मान जैसा शब्द है। हमारी मांग है कि सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की निम्नस्तरीय भाषा का प्रयोग न केवल प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर चोट है। सांसद द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करना उनकी कुंठा और सपा की विकास

विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। मांग है कि मौजूदा विधायक को तत्काल पार्टी से बर्खास्त किया जाए और उनकी सदस्यता भी रद्द की जाए। बिना शर्त देश और प्रधानमंत्री से माफी मांगें' पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि सपा सांसद अपने बयान के लिए बिना शर्त देश और प्रधानमंत्री से माफी मांगें। साथ ही उनके ऊपर संसद के उच्च सिद्धांतों के उल्लंघन को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। संयुक्ता भाटिया ने कहां की प्रधानमंत्री के अपमान से पूरे देश के लोग आहत हैं और उनमें नाराजगी है। प्रधानमंत्री किसी एक दल या समुदाय का नहीं होता है बल्कि पूरे देश का मुखिया होता है। पीएम जैसे संवैधानिक और सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठने वाले व्यक्ति का जो लोग अपमान करते हैं जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

अचलगंज के बदरका प्राथमिक विद्यालय की सहायक शिक्षका

स्कूल में वीडियो बनाया और कीटनाशक खा लिया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

मैं नर्गिस सुल्तान अपने पूरे होशो-हवास में खुदकुशी कर रही हूं। इसके जिम्मेदार पुष्कर बाजपेयी हैं। इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। दो-ढाई साल हो गए पर आठ महीने से तो उसने जीना दुश्वार कर रखा है। हम थक गए हैं। कई बार मेरे मन में आया खुदकुशी कर लूं पर अपने घरवालों के बारे में सोचकर रुक गई। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह खुदकुशी नहीं, मर्डर है। जिसके जिम्मेदार पुष्कर बाजपेयी हैं। अचलगंज के बदरका प्राथमिक विद्यालय की सहायक शिक्षका नर्गिस सुल्तान में स्कूल में वीडियो बनाया और इस तरह की बात कहकर कीटनाशक खा लिया। जिला अस्पताल में उनकी हालत गंभीर है। सदर क्षेत्र के नवीन मंडी के पीछे नव विकसित बस्ती की रहने वाली 40 वर्षीय नर्गिस सुल्तान बदरका प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका हैं। उन्होंने गुरुवार को स्कूल में ही एक वीडियो बना इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर शिक्षण कार्य के दौरान सुबह लगभग 10 बजे कीटनाशक खा लिया। सहयोगी शिक्षक जब तक कुछ समझ पाते वह अचेत होकर जमीन पर गिर गई उनके मुंह से झाग निकलते देख छात्र-छात्राओं व साथी शिक्षकों व कर्मचारियों में खलबली मच गई। विद्यालय की प्रधान शिक्षिका अंजू गुप्ता ने एंबुलेंस से अचलगंज

सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर कीटनाशक खाने की संभावना जता जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रधान शिक्षिका ने बताया कि इसकी की सूचना विभागीय अधिकारियों को दे दी है। जिला अस्पताल में उपचार करने वाले चिकित्सक ने भी नर्गिस सुल्तान के कीटनाशक निगलने की आशंका जताई है। प्रधानाध्यापिका अंजू गुप्ता ने बताया कि अब हालात में सुधार है। आराम होने पर नर्गिस बानो ही बताएगी क्या हुआ था। एसओ बृजेश शुक्ल ने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं आई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बदरका प्रथम में नर्गिस सुल्तान पिछले नौ साल से कार्यरत हैं। वह अविवाहित हैं। उनके पिता बिजली विभाग से जेई पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। भाई फराज खान अधिवक्ता और फैजान खान इंजीनियर हैं। नाजिया ने गुरुवार दोपहर एक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया और स्कूल में ही कीटनाशक खा लिया। नाजिया ने जिस पुष्कर बाजपेई का नाम लिया वह भी स्कूल में ही कार्यरत है। उसी से विवाद की बात वह कह रहीं हैं। शिक्षा मित्र पुष्कर ने बताया कि शिक्षिका नर्गिस उनसे बात नहीं कर रहीं थी।इस वजह से वह भी उनसे बात नहीं करते थे। इस माह मेरा वेतन बढ़कर आया था इसी खुशी में मैंने विद्यालय में गुरुवार को बच्चों को बिस्किट आदि बांटी थी। नर्गिस का बुधवार को ट्रांसफर हो गया था। शायद उन्हें ये लगा हो कि उनके ट्रांसफर पर मैंने विद्यालय में बिस्किट बंटवाया है।

कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। SC ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था। एपेक्स कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामाले में दोबारा सुनवाई करने और 2 महीने में आदेश देने को कहा है। भारत के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। CBI ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई का तर्क था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को राहत देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और अब अंतिम सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया है। पीड़ित के साथ 4 जून 2017 को भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया था। वह अधिकारियों के चक्कर लगाती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच, उसके पिता को पेड़ से बांधकर पीटा गया। पिटाई करने वालों में कुलदीप के भाई अतुल और उनके लोग शामिल थे। इसके बाद 8 अप्रैल 2018 को पीड़ित लखनऊ पहुंची और CM आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने उसे बचा लिया।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे लोकार्पण कराने की तैयारी शुरू

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव/अचलगंज। कानपुर-लखनऊ के बीच 64 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड/ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे (एनई-6) बनकर तैयार हो गया है। प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब इस एक्सप्रेसवे का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण कराने की तैयारी शुरू की है। सूत्रों के अनुसार स्थान तय होने के बाद मुख्यमंत्री भी किसी दिन स्थलीय निरीक्षण करने आ सकते हैं। 24 या 25 मई को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो सकता है। गुरुवार को डीएम घनश्याम मीना, एसपी जयप्रकाश सिंह, एनएचएआई के परियोजना निदेशक परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के आयोजन के लिए कानपुर-लखनऊ हाईवे (एनएच 27) की तरफ उन्नाव और कानपुर के बीच आजाद मार्ग चौराहा और उन्नाव-लालगंज हाईवे पर कोरारी के पास बनाए गए एक्सप्रेसवे कट के पास जनसभा स्थल के लिए जगह देखी। हालांकि अधिकारी अभी प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम घोषित होने या प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसी कोई सूचना मिलने से इन्कार कर रहे हैं। एनएचएआई के पीडी नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि लोकार्पण के 15 से 20 दिन पहले आधिकारिक सूचना जारी होती है। हालांकि बृहस्पतिवार तक कोई सूचना या कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। किसी भी दिन लोकार्पण कराया जा सकता है। इस दौरान पत्रकारों ने गंगा एक्सप्रेसवे, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे और उन्नाव के विकास को लेकर भी सवाल किए। इस पर विधायक ने कहा कि एक्सप्रेसवे केवल सड़क निर्माण परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि ये आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं।

विधायक पंकज गुप्ता ईंधन बचत अपील के बाद काफिले को छोटा करने का ऐलान किया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद अपने काफिले को छोटा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह अब एक ही वाहन का उपयोग करने का प्रयास करेंगे और सप्ताह में एक दिन यात्रा पूरी तरह बंद रखेंगे। विधायक ने यह जानकारी अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। विधायक गुप्ता ने बताया कि वह नगर पालिका अध्यक्ष के समय से ही सीमित संसाधनों का उपयोग करते रहे हैं। उनके स्टाफ की आठ से नौ लोगों की टीम हमेशा दो गाड़ियों से चलती थी और कभी अतिरिक्त वाहन का प्रयोग नहीं किया गया। अब प्रधानमंत्री की अपील के मद्देनजर वह अपने काफिले को और छोटा करते हुए एक वाहन से चलने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि देश इस समय वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हर नागरिक को राष्ट्रहित में ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग में सहयोग करना चाहिए। विधायक ने वैश्विक स्तर पर युद्ध और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का भी जिक्र किया, लेकिन भारत में स्थिति को नियंत्रण में बताया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया। विधायक ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में एकजुट होकर योगदान देने का है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब जनता भी उसमें सहयोग करे। उनके अनुसार, ईंधन बचत केवल आर्थिक मजबूरी नहीं, बल्कि देशभक्ति का भी एक रूप है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र गुतहरा

टीवी भारतवर्ष हाथरस

विद्युत उपकेंद्र गुतहरा पर रविवार को 4 घंटे ठप रहेगी बिजली, मरम्मत कार्य के कारण आपूर्ति रहेगी बाधितगुतहरा (उत्तर प्रदेश): विद्युत उपकेंद्र गुतहरा के अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि सादाबाद से आ रही 33KV मेन लाइन पर पेड़ों की छंटाई और आवश्यक लाइन मेंटेनेंस (मरम्मत) का कार्य किया जाएगा।इस रखरखाव कार्य के कारण दिनांक 17 मई 2026 (दिन रविवार) को सुबह 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप रहेगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे इस अवधि से पहले अपने आवश्यक कार्य निपटा लें।अवर अभियंता राजेंद्र यादव ने सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से धैर्य बनाए रखने, राष्ट्रहित में ऊर्जा की बचत करने और इस कार्य में विद्युत विभाग का सहयोग करने की अपील की है।

लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क

उन्नाव में 21 मई को होने वाली लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक शामिल हुए। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र समय पर पहुंचाने और सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह सक्रिय रखने का आदेश दिया। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन और किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अनुचित सामग्री का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा कर्मियों और कक्ष निरीक्षकों को गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता परीक्षा की शुचिता बनाए रखना है।केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, शौचालय, बैग जमा करने की सुविधा और सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक स्थानों पर महिला पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो कॉपी की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जिससे किसी भी अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। प्रशासन के अनुसार, लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। जनपद में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2688 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुशील कुमार गोंड़, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह, उपजिलाधिकारी सदर, उपजिलाधिकारी सफीपुर और जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

यूपी की चार बड़े लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण में फंसे

योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के कारण अटकती नजर आ रही हैं।जेवर, फर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अब तक तय लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम जमीन अधिग्रहित हो सकी है।

उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में काम कर रही योगी सरकार की चार महत्वाकांक्षी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाएं फिलहाल भूमि अधिग्रहण की धीमी गति के कारण अटकती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मई माह में ही भूमि अधिग्रहण पूरा करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बेहद धीमी चल रही है। कई परियोजनाओं में अब तक 25 प्रतिशत से भी कम भूमि अधिग्रहित हो पाई है, जबकि झांसी लिंक एक्सप्रेस वे में तो अभी तक शून्य प्रगति दर्ज की गई है। इन परियोजनाओं को जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ने सीधे निगरानी शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए, ताकि प्रदेश का एक्सप्रेस वे नेटवर्क और मजबूत हो सके। दो मई को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि चारों लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम मई महीने में ही पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अधिग्रहण की रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है। सोमवार तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार चारों परियोजनाओं के लिए कुल 3678 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, लेकिन अब तक केवल 491 हेक्टेयर भूमि ही अधिग्रहित हो सकी है। चारों परियोजनाओं में सबसे धीमी प्रगति आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे में देखने को मिल रही है। करीब 70 किलोमीटर लंबे इस लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कुल 542 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, लेकिन अब तक केवल लगभग 5 हेक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण हो पाया है। प्रतिशत के हिसाब से यह प्रगति केवल 0.95 प्रतिशत है। यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके बन जाने के बाद आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपस में सीधे जुड़ जाएंगे। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी यूपी तक की यात्रा और अधिक आसान और तेज हो जाएगी। सूत्रों का मानना है कि यह लिंक बनने के बाद व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा फायदा मिलेगा। करीब 115 किलोमीटर लंबे झांसी लिंक एक्सप्रेस वे की स्थिति और भी चिंताजनक है। इस परियोजना के लिए कुल 1183 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, लेकिन अभी तक एक भी हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकी है। यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से उरई (जालौन) के पास शुरू होकर झांसी जिले की गरौठा, टहरौली, मोंठ और सदर तहसीलों से होकर गुजरेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिहाज से यह परियोजना बेहद अहम मानी जा रही है। इस एक्सप्रेस वे के जरिए झांसी और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा, जिससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन को गति मिलने की उम्मीद है।

नमाज अदा करने के लिए मौलाना ने प्रशासन से ट्रैफिक मुक्त सड़क मुहैया कराने की मांग की

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ईद-उल-अजहा से पहले धार्मिक आयोजनों में प्रशासनिक रवैये को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी ने सरकार के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" नारे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कें बंद की जा सकती हैं, तो ईद की नमाज के लिए डेढ़ घंटे का समय देने में आखिर दिक्कत क्या है। मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी ने तीखे लहजे में कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन खुद एक तरफ का रास्ता बंद कर श्रद्धालुओं को निर्बाध आवागमन की सुविधा देता है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं, बल्कि वह इसका समर्थन करते हैं क्योंकि हर धर्म को अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता और सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल तब उठता है जब मुसलमानों की ईद की नमाज को लेकर सख्ती दिखाई जाती है और सड़क पर नमाज की अनुमति तक नहीं दी जाती। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी ने कहा कि "ईद साल में सिर्फ दो बार आती है और नमाज अधिकतम एक से डेढ़ घंटे तक चलती है। ऐसे में प्रशासन अगर थोड़े समय के लिए ईदगाह वाले रास्ते को नियंत्रित कर दे तो इससे किसी को बड़ी परेशानी नहीं होगी। मुफ्ती ने उदाहरण देते हुए कहा कि शहर में रेलवे रोड निर्माण के चलते कई दिनों तक ट्रैफिक डायवर्ट रहता है और सड़कें बंद रहती हैं, फिर धार्मिक आयोजन के लिए सीमित समय की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती।"

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ईंधन संरक्षण अपील पर तंज

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कुछ घंटों बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण अपील पर तंज कसते हुए कहा कि साइकिल, जो सपा का चुनाव चिन्ह है, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। X पर साइकिल चलाते हुए अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए अखिलेश यादव ने हिंदी में लिखा, "अगर आगे बढ़ना है तो साइकिल ही एकमात्र विकल्प है।" केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में वृद्धि पश्चिम एशिया संकट से जुड़े वैश्विक तेल आपूर्ति व्यवधानों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है। हैदराबाद में एक रैली के दौरान, मोदी ने नागरिकों से घर से काम करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके ईंधन बचाने का आग्रह किया, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सके। प्रधानमंत्री की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें मंत्री और अधिकारी दैनिक आवागमन के लिए साइकिल, ई-वाहन और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना अपने आधिकारिक आवास से कार्यालय तक साइकिल से गए, जबकि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया।

एनकाउंटर के बाद आरोपी ने मांगी दया की भीख

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मोनू उर्फ शाहरुख नाम के एक युवक पर नाम बदलकर एक हिंदू नाबालिग युवती को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के उद्देश्य से भगा ले गया था। इसके चलते गुरूवार को शिकायत पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने तुरंत आरोपी के विरूद्ध नाबालिग युवती को भगा ले जाने और धर्म परिवर्तन जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू ही किए थे की 2 घंटे बाद ही पुलिस को सूचना मिली की आरोपी युवती को पुलिस डर के चलते भोपा पुल के पास छोड़कर भागने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए सहावली गांव के पास जब आरोपी को गिरफ्तार करना चाहा तो उसने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में घेराबंदी करते हुए जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें ये शातिर अभियुक्त पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त मोनू उर्फ शाहरुख को पुलिस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, पुलिस ने मौके पर आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दे कि इस दौरान जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो वह हाथ जोड़कर ये कहता हुआ नजर आया कि "साहब मर जाऊंगा लेकिन ऐसा अब कभी नहीं करूंगा।" एनकाउंटर की इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि "आज शाम तकरीबन 6:30 थाना नई मंडी पर थाना क्षेत्र नई मंडी के मखियाली गांव रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दी की उसकी नाबालिग भतीजी को दूसरे धर्म का एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू उर्फ शाहरुख है बहला फुसला कर धर्मांतरण के उद्देश्य से शादी करने के लिए लेकर भाग गया है। यह 12 तारीख के लगभग सुबह 4:00 बजे भागा था। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण तथा धर्म परिवर्तन कठोर मुकदमे में अभियोग पंजीकृत किया और तत्काल युवती की बरामदगी के लिए और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन करके क्षेत्र में रवाना कर दिया गया। टीमों के लगातार प्रयास से मात्र दो घंटे के भीतर अपहृत युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया।